भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5460

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

झांसी में जल निकायों की सफाई

5460. श्री अनुराग शर्मा:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झांसी और ललितपुर में अब तक साफ किए तालाबों, झीलों और कुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) झांसी और ललितपुर में भूमिगत जल में सुधार हेतु उठाए गए कदमों और तालाबों, झीलों और कुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) झांसी और ललितपुर में पेयजल पाइप लाइन प्रदान करने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) जल संसाधन के विकास और प्रबंधन से संबंधित निर्माण कार्यों की आयोजना, निधियन, निष्पादन और अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधन और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता देने के लिए भारत सरकार, विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के सतत विकास और दक्ष प्रबंधन को बढ़ावा देने हेत तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत झांसी और ललितपुर जिले में परंपरागत जल निकायों के निर्माण कार्यों के नवीकरण तथा जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं के ब्यौरे के नीचे दिए गए हैं:-

मद	जिला	
	झांसी	ललितपुर
परंपरागत जल निकायों के नवीकरण निर्माण कार्य	914	1984
जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं	3240	4903

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना (पीएमकेएसवाई) की जल निकायों की आरआरआर संबंधी स्कीम के अंतर्गत ललितपुर के 12 जल निकायों के समूह तथा 8 जल निकायों (झांसी के 3 जल निकायों सहित) को शामिल किया गया है। इन जल निकायों के समूह हेतु क्रमशः 1.05 करोड़ रूपए तथा 15.36 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि झांसी और ललितपुर जिले में क्रमशः 109 (कार्य कर रही- 100; आंशिक रूप से कार्य कर रही- 4; बंद- 5) और 58 (कार्य कर रही- 48; कार्य नहीं कर रही- 10) पाईप्ड पेयजल स्कीमें कार्य कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त, ललितपुर की 3 जलापुर्ति स्कीमों को भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक इन स्कीमों के लिए 37.34 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।

*****